समाचार वाणी
ख़बर जो करें असर !

नाशिक | Saturday, 17 October 2026

11 अक्टूबर को किसानों को मिलेगा दिवाली गिफ्ट, केंद्र सरकार देगी 42,000 करोड़ की सौगात

Publisher

Published on 10 Oct 2025

केंद्र सरकार ने किसानों के लिए इस दिवाली एक बड़ा तोहफा तैयार किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 अक्टूबर को देशभर के किसानों को 42,000 करोड़ रुपये से अधिक की आर्थिक सौगात देने वाले हैं। यह घोषणा न केवल किसानों के चेहरे पर मुस्कान लाएगी बल्कि आने वाले त्योहारी सीजन से पहले ग्रामीण अर्थव्यवस्था में नई जान फूंक देगी। सरकार इस राशि को विभिन्न कृषि योजनाओं और प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (Direct Benefit Transfer) के माध्यम से किसानों के खातों में पहुंचाने की तैयारी कर रही है।

जानकारी के अनुसार, इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किसानों को संबोधित करेंगे और देशभर में आयोजित कार्यक्रमों के जरिए किसानों तक संदेश पहुंचाया जाएगा। यह रकम मुख्य रूप से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN) की अगली किस्त और कुछ नई कृषि आधारित योजनाओं के तहत दी जाएगी। पीएम-किसान योजना के तहत अब तक किसानों को हर चार महीने में 2,000 रुपये की किस्त दी जाती रही है, जो सीधे उनके बैंक खातों में ट्रांसफर की जाती है। अब सरकार 15वीं किस्त के साथ-साथ अन्य योजनाओं की धनराशि भी जारी करेगी।

कृषि मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के अनुसार, इस राशि का वितरण देश के लगभग 8 करोड़ किसानों को लाभान्वित करेगा। यह रकम सीधे डीबीटी के माध्यम से किसानों के बैंक खातों में जाएगी, जिससे किसी भी तरह की बिचौलिया समस्या से बचा जा सके। इसके साथ ही सरकार किसानों के लिए नई योजनाओं की शुरुआत भी कर सकती है, जिनमें फसल बीमा, जल संरक्षण और कृषि यंत्रीकरण को बढ़ावा देने वाली योजनाएं शामिल हो सकती हैं।

सरकार का यह कदम कृषि क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने के साथ-साथ किसानों की आमदनी बढ़ाने के उद्देश्य से उठाया गया है। बीते कुछ वर्षों में सरकार ने किसानों के लिए कई योजनाएं लागू की हैं, जिनमें पीएम-किसान, पीएम फसल बीमा योजना, कृषि अवसंरचना निधि और मृदा स्वास्थ्य कार्ड जैसी योजनाएं प्रमुख हैं। इन योजनाओं ने किसानों के जीवन स्तर में सुधार लाने और

कृषि उत्पादकता को बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई है।

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह घोषणा आगामी विधानसभा चुनावों से पहले किसानों को साधने की कोशिश के रूप में भी देखी जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी पहले भी किसानों के कल्याण को सरकार की प्राथमिकता बताते रहे हैं। उन्होंने कई बार अपने भाषणों में कहा है कि भारत की आत्मनिर्भरता किसानों की समृद्धि से ही संभव है।

केंद्र सरकार इस मौके पर 'किसान संवाद कार्यक्रम' भी आयोजित करने जा रही है, जिसमें लाखों किसान ऑनलाइन और ऑफलाइन माध्यम से जुड़ेंगे। कार्यक्रम के दौरान किसानों को नई कृषि तकनीकों, जैविक खेती, और जलवायु परिवर्तन से जुड़ी खेती के तरीकों पर भी जानकारी दी जाएगी। सरकार का लक्ष्य किसानों को आधुनिक कृषि पद्धतियों से जोड़ना और उनकी उत्पादन लागत को कम करना है।

वित्त मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार, इस 42,000 करोड़ रुपये की राशि में से लगभग 20,000 करोड़ रुपये प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत जारी किए जाएंगे, जबकि शेष राशि कृषि अवसंरचना, सिंचाई और बीमा योजनाओं में उपयोग की जाएगी। यह धनराशि राज्यों को भी दी जाएगी ताकि वे अपने स्तर पर कृषि सुधार कार्यक्रमों को लागू कर सकें।

कई किसान संगठनों ने सरकार के इस कदम का स्वागत किया है। उनका कहना है कि इस प्रकार की सहायता से किसानों की वित्तीय स्थिति मजबूत होगी और ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियों में तेजी आएगी। हालांकि, कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि केवल वित्तीय सहायता से समस्या का समाधान नहीं होगा, बल्कि दीर्घकालिक कृषि नीति की आवश्यकता है जिसमें जल प्रबंधन, फसल विविधीकरण और बाजार सुधार जैसे मुद्दों को प्राथमिकता दी जाए।

दिवाली से ठीक पहले आने वाली इस घोषणा से निश्चित रूप से किसानों के चेहरे पर मुस्कान लौटेगी। यह पहल न केवल सरकार की 'सबका साथ, सबका विकास' की नीति को सशक्त बनाती है, बल्कि यह संदेश भी देती है कि भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ – हमारे किसान – देश की प्राथमिकता हैं।

प्रधानमंत्री मोदी की इस घोषणा से किसानों के बीच उम्मीद की नई किरण जगी है। यह सौगात देश के कृषि क्षेत्र को मजबूती देने की दिशा में एक बड़ा कदम साबित हो सकती है, जिससे भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था और आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को नई गति मिलेगी।

DISCLAIMER: the views/contents expressed/presented herein, within this advertorial and promotional feature are the sole and exclusive responsibility of individual clients/expert/their authorised representative/Publisher, to which effect, publication house/its representative/affiliates are not responsible/liable whatsover.